जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 48 संख्याः 129 प्रभात कोटा, मंगलवार 21 फरवरी, 2023 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

''मां का लाडला'' सुना होगा पर ऐसा नहीं जैसा किलर व्हेल का होता है। इस प्रजाति में मादा अपनी नर संतान के अच्छे भविष्य के लिए अपनी प्रजनन संभावनाओं का भी बलिदान कर देती है। ''मां के लाड़ले'' की अवधारणा को मादा ओरका (किलर व्हेल) चरम पर ले जाती हैं। वो अपने बेटों की वयस्क होने तक देखभाल करती हैं, भले ही इससे उनके प्रजनन के अवसर खत्म हो जाएं। जर्नल करंट बायॉलटी के 8 फरवरी के संस्करण में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने मां -बेटे के इस रिश्ते का अध्ययन किया। उन्होंने वॉशिंगटन स्टेट और ब्रिटिश कोलम्बिया के बीच रहने वाले ओरका समूह (सदर्न रैज़िडैंट्स) की 73 व्हेल्स पर यह शोध किया। वर्ष 1976 से ही सैंटर फॉर व्हेल रिसर्च, हार्बर वॉशिंगटन, के शोधकर्ता इस समूह पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने यहां एक अलग सोशल सिस्टम देखा कि, अपने वयस्क पुत्रों के लिए भी मां ही शिकार करती है। शोध के प्रथम लेखक माइकल वाइज़, जो व्हेल रिसर्च सैंटर के डायरैक्टर हैं, ने कहा, ओरका मातृ सत्तात्मक समाज है, बेटे और बेटी दोनों अपना सारा जीवन मां के समूह में ही रहते हैं। लेकिन बेटों का मां से ज्यादा मजबूत रिश्ता होता है, वे प्रायः मां के आगे पीछे घूमते रहते हैं। मां से चिपके रहने का उन्हें फायदा भी होता है। इसके विपरीत बेटी को वयस्क होते ही मां अलग कर देती है और उसे अपने लिए स्वयं भोजन जुटाना पड़ता है। आमतौर पर व्हेल 6 से 10 साल में वयस्क हो जाती हैं। सवाल यह है कि, मादा ओरका बेटों को ज्यादा और बेटी को कम तवज्जो क्यों देती हैं। वाइज़ ने कहा, आकार में नर मादा से बड़े होते हैं और उन्हें ज्यादा कैलरी की जरुरत होती है तथा उनमें चतुराई भी कम होती है, इसलिए मछली पकड़ने में प्रायः असफल रहते हैं, शायद इसीलिए मां उनकी मदद करती है और बेटियां प्रजनन करती हैं। बेटियों के बच्चे भी उसी समूह में रहते हैं, अर्थात् एक और खाने वाला बढ़ जाता है। इसलिए बेटी की मदद करना व्हेल मदर को भारी पड़ता है, जबकि बेटे जब प्रजनन करते हैं तो उनके बच्चे अपनी माँ के साथ किसी और समूह में रहते हैं। वाइज़ ने कहा, उद्विकास में भी ऐसे ही लाभ मिलते हैं, जब आपके जीन्स नई पीढ़ी में जाते हैं और आपको किसी के पालन पोषण की जिम्मेवारी भी नहीं उठानी पड़ती। लेकिन इसकी कीमत मां को चुकानी पड़ती है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वयस्क पुत्र की देखभाल करने वाली मां की प्रजनन संभावना कम हो जाती है।

अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडन अचानक यूक्रेन पहुंचे

यूक्रेन वॉर को एक साल होने को हैं और विश्वभर में कूटनीतिक गतिरोध अधिक खतरनाक होता जा रहा है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। अगर एक साल तक चले युद्ध की गहराई में जायें, तो हम पायेंगे कि वैश्विक कूटनीतिक गतिरोध बहुत तीक्ष्ण और खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया संकट के कगार के इर्द-गिर्द पहुँच चुकी है।

राष्ट्रपति जो बाइडन सोमवार को एकाएक युद्ध पीड़ित यूक्रेन की राजधानी कीव पहुँच गये, वहीं चीन के शीर्ष कूटनीतिज्ञ तथा शी जिनपिंग के मुख्य विदेश नीति सलाहकार, वांग यी मॉस्को जाने वाले हैं।

इसी बीच, अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ब्लिंकन तथा चीन के नये ताकतवर राजनयिक के रूप में उभरे वांग यी के बीच हुई मीटिंग दोनों सुपर पावर्स के बीच पैदा हुये नये संदेहों तथा आरोपों के साथ खत्म हो गई।

वांग की यह यूरोप यात्रा अमेरिका के यूरोपीय मित्र देशों को प्रभावित करने के चीन के मोहक किन्तु आक्रामक प्रयास का एक हिस्सा है। वांग यी चीन को यूरोप में शान्ति लाने के लिये प्रयासरत एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। वांग यी ने इससे पहले हाई प्रोफाइल म्यूनिख सिक्योरिटी

- **चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मुख्य विदेश नीति सलाहकार वांग यी भी मॉस्को जा रहे हैं।**
- **वांग इससे पहले यूरोप भी गए थे, अमेरिका के यूरोपियन मित्रों का भरोसा जीतने के लिए। उनकी कोशिश यह बताना है कि, चीन यूरोप में शांति स्थापना के प्रति ईमानदार है।**
- **चीन की कोशिश असल में पश्चिमी एकता को तोड़ने की है, इसके लिए वह यूरोपियन देशों को चीन के विशाल बाज़ार का प्रलोभन भी दे रहा है।**

कॉन्फ्रैंस को संबोधित कर घोषणा की थी कि यूक्रेन संकट का चीन एक समग्र समाधान प्रस्तुत करेगा। तथापि, उसके म्यूनिख में दिए बयान को सही मान लिया जाए तो उन्होंने एक तरह से इसके लिए चीन रूस को घातक हथियार सप्लाई करने की तैयारियां कर रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने वांग यी के साथ एक विशेष बातचीत की, जिसके बाद दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव और व्यापक संदेह पैदा कर दिए हैं कि यूक्रेन के दीर्घकालिक युद्ध में चीन रूस की सहायता करने का आधार निर्मित कर रहा है। अमेरिका ने म्यूनिख कॉन्फ्रैंस में कहा था कि युद्ध भूमि में तैनात करने के लिए चीन रूस को घातक हथियार सप्लाई करने की तैयारियां कर रहा है। बढ़ गया।

वांग यी ने यूरोप के नेताओं से कहा था कि चीन आग में घी डालने का काम नहीं करेगा और वह यूक्रेन के दीर्घ युद्ध से किसी प्रकार का लाभ उठाने के विरूद्ध है। यह इशारा अमेरिका के लिए था, क्योंकि चीन ने अपने प्राइम टाइम प्रसारणों में यह बात कही है कि अमेरिका यूक्रेन के युद्ध को लम्बा खींचना चाहता है ताकि उसकी हथियार इण्डस्ट्री को हथियारों की बिक्री से मुनाफा हो सके।

चीन ने यूरोप के देशों से भी अनुरोध किया है कि वे अपनी ''सामरिक स्वतंत्रता'' पर जोर दें और उसी के अनुरूप काम करें। इसका संदर्भ यह है कि यूरोप के देश अमेरिका के इशारे पर काम कर रहे हैं और उसके सामरिक उद्देश्यों को आगे बढ़ा रहे हैं।

चीन के कूटनीतिक प्रहार का उद्देश्य एटलांटिक महासागर के पार के देशों के बीच अलगाव पैदा करना और

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तमिलनाडू ने ''नीट'' की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

तमिलनाडू सरकार ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की तथा कहा कि, देशभर के मैडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एक ही टैस्ट आयोजित करना संघवाद के खिलाफ है

-लक्ष्मण वेंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले तमिलनाडु सरकार, नैशनल एलिजिबिलिटी कम ऐन्ट्रैंस टैस्ट (एन.ई.ई.टी.) अर्थात् ''नीट'' जो मैडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिये राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, के मुद्दे पर एक बार फिर केन्द्र सरकार के आमने-सामने हो गई है। अब तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर नीट की वैधता को चुनौती दी है।

तमिलनाडु सरकार तथा सत्तारूढ़ द्रमुक मैडिकल कोर्सों के लिए केन्द्रीयकृत प्रवेश परीक्षा के खिलाफ रही हैं। उनका कहना है कि यह संघवाद के सिद्धांत के विरूद्ध है तथा यह (परीक्षा) इस सिद्धांत का पूरी तरह उल्लंघन करती है। हालाँकि केन्द्र सरकार इस बात को पूरी तरह स्पष्ट कर चुकी है कि यह परीक्षा मानकीकरण (स्टेडन्डाइजेशन) तथा कैपिटेशन फीस के जरिये होने वाले प्रवेशों से संबंधित भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक राष्ट्रीय आवश्यकता है, लेकिन तमिलनाडु सरकार नीट का तभी से विरोध कर रही है, जब 2019 में यह सत्ता में आई थी। यही नहीं, जब द्रमुक विपक्ष में थी, तब भी इसने नीट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। अब, सरकार को यह मालूम है कि अदालत का फैसला किसी भी पक्ष में जा सकता है लेकिन फिर भी वह इस

- **एम. के. स्टालिन ने 2019 में तमिलनाडू में सरकार बनाई थी, तब से ही वे ''नीट'' के विरोधी रहे हैं।**
- **हालांकि, स्टालिन जानते हैं कि, कोर्ट का फैसला किसी भी पक्ष में जा सकता है, पर वे राज्य में नीट विरोधी जनभावना को भुनाने के लिए इस मुद्दे को जीवित रखना चाहते हैं।**
- **ज्ञातव्य है कि, सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2020 से ही नीट को वैध ठहरा चुका है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, भारी धनराशि लेकर मैडिकल कॉलेज में प्रवेश देने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए ''नीट'' जरूरी है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दिल्ली धर्म संसद की रिपोर्ट मांगी सुप्रीम कोर्ट ने

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से वह चार्जशीट माँगी है, जो दिसम्बर 2021 में दिल्ली में आयोजित धर्म संसद में दिये गये कथित उत्तेजक एवं भड़काऊ भाषणों के सिलसिले में दी गई थी। पुलिस

- **चीफ जस्टिस डी. वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय बैंच ने यह आदेश तब दिया, जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि, वह अभी भी फॉरैंसिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है।**

ने कहा है कि उसे फॉरैन्सिक रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्द्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा एवं जे.बी. पारदीवाला की बैंच ने यह आदेश उस समय दिया, जब दिल्ली पुलिस की ओर से प्रस्तुत हुये एडिशनल सॉलिसिटर के.एम.नटराज ने कहा कि सैम्पल

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मुम्बई की तर्ज पर दिल्ली में भी बाइक टैक्सी पर रोक

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। गोवा में पिछले कई वर्षों से बाइक टैक्सीज़ की अनुमति है, लेकिन दिल्ली या मुम्बई में नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसके लिए लायसैंस जारी करने से

- **ज्ञातव्य है कि, महाराष्ट्र सरकार ने रैपिडो बाइक टैक्सी को लाइसैंस देने से मना कर दिया। कम्पनी ने इस पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, वहां से भी इसे राहत नहीं मिली। अब दिल्ली ने भी यही कदम उठाया है।**

इन्कार किए जाने के विरूद्ध इस माह की शुरुआत में बाइक टैक्सी सेवा समूह केन्द्र ''रैपिडो'' को राहत देने से इंकार कर दिया था।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.), जस्टिस जे.बी. पारदी वाला की बैंच ने टिप्पणी की थी कि वर्ष 2019 में मोटर व्हीकल एक्ट में किए

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

महाधिवेशन से तीन दिन पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी नेताओं पर ई.डी. की रेड

कांग्रेस ने कहा, यह डराने धमकाने की कार्यवाही है, पर इससे महाधिवेशन नहीं रूकेगा, वो हो के रहेगा

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तीन दिन बाद होने जा रहे ए.आई.सी.सी. महाधिवेशन से पूर्व की गई यह कार्यवाही यह स्पष्ट रूप से एक प्रतिशोधी कार्रवाई प्रतीत होती है। एन्फोर्समैन्ट डायरैक्टोरेट (ई.डी.) ने कांग्रेस नेताओं से जुड़े परिसरों सहित छत्तीसगढ़ के कई ठिकानों पर आज छापे मारे।

यद्यपि ई.डी. अधिकारियों का दावा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कोल लेवी से अर्जित धन को लेकर चल रही जांच का हिस्सा है, लेकिन इन रेड्स का समय यह काफी कुछ स्पष्ट करता है कि वित्त मंत्रालय द्वारा नियंत्रित इस केन्द्रीय जांच एजेंसी की कार्यवाही ए.आई.सी.सी. महाधिवेशन की तैयारियों में बाधा डालने और परेशान करने के लिए की गई है।

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व काल एक कांग्रेस शासित राज्य है। यहां की राजधानी रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का महाधिवेशन आयोजित किया जा रहा है और रेड्स उसे तीन दिन पूर्व मारी गई है। कांग्रेस महासचिव एवं संचार प्रभारी जयराम रमेश ने ए.आई.सी.सी. मुख्यालय पर मीडिया कर्मियों को ब्रीफ करते हुए कहा कि पार्टी के पांय या छह सीनियर नेताओं के यहां डाली गईं रेड्स लोकतंत्र के लिए विनाशक है। उन्होंने बताया कि रेड्स तड़के सुबह पांच बजे तक जारी रहीं।

रमेश ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से प्रतिशोधी एवं परेशान करने वाली राजनीति है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन के लिए यह आंखे खोलने वाली हो सकती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ''हम भयभीत नहीं हैं। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं हैं। हम नहीं डरेंगे। मैंने बार-बार कहा है कि एफ.डी.आई. की मोदी की पॉलिसी कपटपूर्ण एवं भयभीत करने वाली हैं। यही वास्तविक एफ.डी.आई. पॉलिसी

- **ई.डी.के अधिकारियों ने कहा कि, यह कार्यवाही कोयला लेवी में गड़बड़ी की जांच और मनी लॉण्डरिंग के मामले में की गई है। लेकिन रेड की टाईमिंग को लेकर राजनैतिक हल्कों में सवालिया चिन्ह लगाया जा रहा है।**
- **नई दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, जयराम रमेश ने कहा कि, यह प्रतिशोध, उत्पीड़न की राजनीति है, पर हम डरे नहीं हैं।**
- **सूत्रों ने बताया कि, दर्जन भर स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिसमें कांग्रेस नेताओं के परिसर भी शामिल हैं, रेड कब तक चलेगी यह अभी पता नहीं है।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में ट्रम्प अभी भी रिपब्लिकन्स की पहली पसंद हैं

हाल ही में हुए हारवर्ड कैप्स-हैरिस पोल में लगभग 46 प्रतिशत लोगों ने ट्रम्प को चुना

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प जब से राष्ट्रपति पद से हटे हैं, तभी से वे विभिन्न कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं- चाहे उनके कारोबारी सौदों की जाँच है, 2020 के चुनावों में दखलंदाजी की कोशिशें की जाँच हो या फिर उनके पास बरामद हुई बहुत सी क्लासीफाइड फाइलों की डिपार्टमैंट ऑफ जस्टिस द्वारा की जा रही जाँच हो, फिर भी वे 2024 के चुनाव के लिए रिपब्लिकन प्रत्याशी बन सकते हैं।

अगले वर्ष होने वाले चुनावों में, ट्रम्प एक बार फिर वाइट हाउस में पहुँचने तथा जो बाइडन से सत्ता छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके लिये, उन्हें पहले पार्टी-प्राइमरीज में रिपब्लिकन्स समर्थन जीतना होगा।

अगर नये चुनाव को किसी संकेत के रूप में लिया तो पार्टी प्रत्याशी के रूप में रिपब्लिकन्स की पसंद में सबसे आगे रहने की ट्रम्प की संभावना सुस्पष्ट है।

हार्वर्ड कैप्स-हैरिस पोल के अनुसार, 15 तथा 16 फरवरी को हुये पोल में, 1800 से अधिक रजिस्टर्ड मतदाताओं में करीब आधे प्रतिक्रिया दाताओं ने ट्रम्प का समर्थन किया। ट्रम्प ने इस सर्वे में अपने अपुष्ट प्रतिद्वंदी तथा फ्लोरिडा के गवर्नन रॉन डीसैन्टिस से दुगुने वोट हासिल किये।

सर्वे में रिपब्लिकन मतदाताओं से पूछा गया था कि अगर 2024 जी.ओ.पी. प्रैसिडेन्शियल प्राइमरी आज सम्पन्न हो, तो वे किस प्रत्याशी को समर्थन देंगे। करीब आधे, 46 प्रतिशत मतदाताओं ने ट्रम्प का चयन किया। डीसैन्टिस, 23 प्रतिशत समर्थन के साथ, ट्रम्प से बहुत दूर किन्तु दूसरे स्थान पर रहे। उन्हें पहले पोल से मामली से कम वोट मिले। पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेन्स 7 प्रतिशत मतों के साथ तीसरे स्थान पर तथा साउथ केरोलिना की गवर्नर निक्की हैली 6 प्रतिशत मतों के साथ चौथे स्थान पर रहीं। उन्हें पहले से कुछ ज्यादा वोट मिले। हैली ने पिछले सप्ताह वाइट हाउस की अपनी दौड़ वाले पहले तथा इस प्रकार ट्रम्प को चुनौती देने वाले पहले रिपब्लिकन नेता के रूप में सामने आईं। इसी पोल में रिपब्लिकन प्रतिक्रिया दाताओं से यह भी पूछा गया था कि अगर ट्रम्प 2024 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में नहीं रहते हैं तो वे किसे वोट देंगे। 39 प्रतिशत के साथ लोगों ने डीसैन्टिस, उनके बाद 17 प्रतिशत लोगों ने पेन्स, 10 प्रतिशत लोगों ने हैली तथा 5 प्रतिशत लोगों ने टैक्सास सीनेटर टेड क्रुज का चयन किया।

हैरिस पोल में आधे से अधिक, 57 प्रतिशत प्रतिक्रिया दाताओं ने कहा कि वे राष्ट्रपति जो बाइडन की ''पद के लिये फिटनैस'' को लेकर संदेह में हैं। अमेरिका के सामने खड़ी बड़ी चुनौतियों के रूप में महँगाई, अर्थव्यवस्था तथा रोजगार चिन्हित किये गये। केवल एक-तिहाई मतदाताओं ने ही यह कहा कि देश सही राह पर अग्रसर है।

- **उनके निकटतम प्रतिद्वंदी फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसैन्टिस को ट्रम्प से आधे, मात्र 23 प्रतिशत वोट मिले, वे दूसरे स्थान पर रहे।**
- **पर्व उपराष्ट्रपति को 7 प्रतिशत लोगों ने प्राथमिकता दी, पर भारतीय मूल की साउथ कैरोलाइना गवर्नर निकी हैली 6 प्रतिशत वोट के साथ चौथे स्थान पर रहीं। निकी ने पिछले सप्ताह ही अपनी उम्मीदवारी घोषित की थी।**
- **सर्वे में यह पूछा गया कि, अगर ट्रम्प नहीं तो कौन? इस पर 39 प्रतिशत ने डीसैन्टिस को चुना और सिर्फ 10 प्रतिशत ने हैली के प्रति रूझान व्यक्त किया।**

'गोधरा कांड के अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 फरवरी। गुजरात सरकार ने सोमवार को उन 11 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिये जाने का आग्रह किया, जिन्हें 2002 के गोधरा में ट्रेन देने वाले केस में दिये गये मृत्युदंड को गुजरात उच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास में बदल दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी.वाय. चन्दूचूड़ तथा

- **गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका में आग्रह किया। ज्ञातव्य है कि, गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा कांड के मृत्युदंड प्राप्त 11 दोषियों की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया था।**

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)